तिब्बत देश

2009 और चीन : भस्मासुर का 'समारोह वर्ष'

चीन सरकार के लिए 2009 वर्ष बाकी वर्षों के मुकाबले बहुत अलग है। इस साल की एक अक्तूबर से ठीक 60 साल पहले चेयरमैन माओ के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी ने चियांग काई शेक की राष्ट्रवादी सरकार का तख्ता पलटकर नए 'पीपल्स रिपब्लिक आफ चायना' की स्थापना की थी। मार्च 2009 का महीना चीनी शासकों के लिए बहुत विशिष्ठ यादों वाला था क्योंकि चीनी सेना ने इसी महीने में तिब्बत पर चीन के कब्जे का आखिरी अध्याय लिखा था। मार्च 1959 में तिब्बत की जनता के स्वतंत्रता अभियान को कुचल कर और वहां के शासक दलाई लामा को भागकर भारत में शरण लेने पर मजबूर करके चीनी सेना ने पूरे तिब्बत पर चीनी कब्जे की दस साल से चल रही उपनिवेशवादी प्रक्रिया को पूरा किया था।

ठीक इसी अंदाज़ में जून 1989 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में चीनी सेना ने बीजिंग के तिएन अनमन चौक में फौजी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के बूते पर चीनी युवाओं के लोकतंत्र आंदोलन को कुचलने में सफलता पायी थी। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के इस अभियान ने कितने हजार चीनी युवाओं की जान ली, यह आज भी रहस्य बना हुआ है। 2009 वर्ष को तिब्बत में विदेशी चीनी शासन के विरोध में 1989 में उठे तिब्बती आंदोलन और उसे फौज के बूते पर कुचलने की 20वीं वर्षगांठ के लिए भी याद किया गया। चीन के वर्तमान शासनाध्यक्ष हू जिंताओ ने तब तिब्बती प्रदर्शनों को कुचलने के लिए फौजी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का सफल प्रयोग किया था । हू जिंताओ के उसी 'ल्हासा मॉडल' का इस्तेमाल तीन महीने बाद तिएन अनमन चौक की चीनी लोकतांत्रिक क्रान्ति को कुचलने के लिए किया गया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को कामरेड हू जिंताओ के इस 'उपहार' के कारण ही उन्हें पार्टी के केंद्रीय सत्ता दायरे में शामिल करने वाला ईनाम मिला था जहां से वह आज सबसे ऊंचे पद पर पहुंचे हैं।

लेकिन 2009 का साल चीनी शासकों के लिए एक ऐसी 'सफलता' की भी 60वीं सालगिरह है जिसे ऊंचे सुर में गाकर नहीं बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर गुपचुप मुस्कराकर याद किया जाता है। 1949 में चीन की सत्ता में आने के तुरंत बाद कामरेड माओ ने पूर्वी तुर्किस्तान (चीनी नाम 'शिंजियांग' या 'सिंकियांग') के ऐसे हर छोटे बड़े नेता को बीजिंग आकर बात करने का स्नेह भरा न्यौता भेजा जो पूर्वी तुर्किस्तान की आजादी की मांग करता था। उनके लिए बीजिंग से एक विशेष विमान भेजा गया। लेकिन वे नेता उसके बाद फिर कभी अपने देश वापस नहीं आए। रास्ते में ही एक रहस्यमय बम विस्फोट से वह विमान और उसमें सवार पूर्वी तुर्किस्तान का पूरा नेतृत्व अपने देश की आजादी के सपनों के साथ ही नष्ट हो गया। उसके बाद के साठ साल में अब पहला मौका है जब पूर्वी तुर्किस्तान में राष्ट्रीय स्तर पर सुश्री राबिया कादिर के रूप में कोई उइगुर नेता आजादी के लिए खड़ा हो पाया है। यह बात अलग है कि चीन सरकार पूरे दम के साथ सुश्री कादिर को एक 'आतंकवादी' बताने में जुटी हुई है।

अब जबकि चीन सरकार इस तरह की लगभग सभी वर्षगांठों को मना चुकी है, यह देखना रोचक होगा उसने इन वर्षगांठों को किस अंदाज़ में मनाया? पिछले साल बीजिंग ओलंपिक की चकाचौंध से अभिभूत दुनिया भर के लोग यह उम्मीद लगाए हुए थे कि चीनी जन गणराज्य की स्थापना की 60वीं सालगिरह पर चीनी जन और दुनिया भर के गण को आमंत्रित किया जाएगा। लेकिन ठीक उलटे अंदाज़ में इस समारोह को किसी फौजी छावनी के समारोह की तरह ऐसे नियंत्रित तरीके से मनाया गया कि उसमें चीनी राजधानी बीजिंग के नागरिकों के शामिल होने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया।

समारोह के आसपास की बस्तियों में कर्फ्यू लगा दिया गया और लोगों को हुक्म दिया गया कि वे गलियों में आने के बजाए घर के भीतर टीवी पर ही इन समारोहों को देखें। यहां तक कि समारोह वाली सड़कों पर बसे घरों की खिड़कियां बंद कराकर सड़कों पर तैनात पुलिस और सैनिकों को आदेश दे दिया गया कि खिड़कियों से झांकने या छज्जों पर आने वाले लोगों को गोली मार दी जाए। इस सबके पीछे 'देशभक्ति' भरी यह दलील दी गई कि देश में मौजूद 'अलगाववादी, आतंकवादी और विदेशी एजेंट' इन समारोहों को असफल करने पर तुले हुए हैं। समारोह से महीनों पहले से ऐसे सब चीनी नागरिकों को जेल में बंद करने या बीजिंग से दूर भेजने का अभियान चल रहा था जिन पर किसी लोकतंत्रवादी, फालुन गांग, ईसाई, मुस्लिम या किसी तिब्बती संगठन से जुड़े होने की आशंका थी। जून 2009 में तिएन अनमन नरसंहार की बीसवीं सालगिरह के आसपास के दिनों में इस टूरिस्ट इलाके को हजारों वर्दीधारी सैनिक और खुफिया पुलिए एजेंट तैनात करके एक फौजी छावनी में बदल दिया गया था।

उधर तिब्बत में 10 मार्च को 1959 की तिब्बती जनक्रान्ति की 50वीं सालगिरह पर 'तिब्बत मुक्ति' समारोह हुए पर उनसे तिब्बती जनता को दूर और घरों में बंद रखा गया। लेकिन इसके बावजूद दर्जनों जगह पर तिब्बती आजादी के मतवालों ने अचानक प्रदर्शन करके चीनी प्रशासन को हैरान किया। चीन सरकार की उपनिवेशवादी बेहूदगी तब अपने चरम रूप में दिखी जब दलाई लामा के चीन से भागकर भारत में शरण लेने को पूरे चीन में 'दासता मुक्ति दिवस समारोह' के रूप में मनाया गया। उस दिन तिब्बती आबादी वाले सभी प्रांतों में राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे किसी अवसर पर तिब्बती जनता फिर से पिछले साल की तरह कोई प्रदर्शन न करे, 'तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र' से बाहर तिब्बत के खम और आम्दो प्रांतों वाले युन्नान, सिचुआन, चिंघाई और गांसू चीनी प्रांतों के कस्बों को फौजी छावनियों में बदल दिया गया। मार्च के बाद सात महीने बीतने पर भी इन कस्बों में चीनी सेना अभी तक तैनात है।

लेकिन चीन के लोकतंत्रवादियों और तिब्बतियों के मुकाबले यह साल पूर्वी तुर्किस्तान की जनता के लिए कहीं ज्यादा दुर्भाग्यशाली रहा। राजधानी उरुमची, काशगर और काशी समेत कई शहरों में इस साल जुलाई में तिब्बती सेना, पुलिस और वहां चीन से लाकर बसाए गए हान युवाओं ने 800 से ज्यादा उइगुरो की हत्या कर दी। मारे गए उइगुर मुसलमानों का दोष यह था कि उनमें से कुछ लोगों ने यह मांग की थी कि 25 जून के दिन चीन के कैंटन शहर में हान मजदूरों द्वारा आठ उइगुर युवाओं की सरेआम हत्या की जांच की जाए। चीनी शासन द्वारा इस अंदाज़ में अपनी 'राष्ट्रीय सालगिरह' मनाने की अपनी इस अदा पर चीनी शासक भले ही खद को शाबायी दे लें, पर उनके भीतर का यह भस्मासुर न केवल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बल्कि पूरे चीन के विनाश के बीज पाले हुए है।

— विजय क्रान्ति

राष्ट्रपति ओबामा ने दलाई लामा से मिलने अपना प्रतिनिधिमंडल धर्मशाला भेजा

चीन सरकार आग बबूला, अमेरिकी जनमत ओबामा–दलाई लामा मुलाकात के पक्ष में

वाशिंगटन, 14 सितंबर परमपावन दलाई लामा के कार्यालय ने आज इस बात की पुष्टि की कि 13 और 14 सितंबर को धर्मशाला में दलाई लामा और अमेरिकी सरकार के एक उच्चाधिकार प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत हुई। प्रतिनिधिमंडल की नेता वेलेरी जेरेट थीं। जेरेट इंटरगवर्नमेंटल अफेयर्स और पब्लिक एंगेजमेंट के मामलों में राष्ट्रपति की वरिश्ठ परामर्शदाता और सहायक हैं। प्रतिनिधिमंडल में लोकतंत्र एवं वैश्विक मामलों की अवर राज्य मंत्री मारिया ओटेरो और अमेरिकी सरकार के अन्य अधिकारी शामिल थे। उल्लेखनीय है कि मारिया ओटेरो तिब्बती मामलों की विशेष संयोजक के रूप में काम कर रही हैं।

सुश्री जेरेट ने परमपावन को व्यक्तिगत रूप से यह संदेश दिया कि राष्ट्रपति ओबामा ''तिब्बती धर्म, भाषा और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा तथा मानवाधिकारों एवं नागरिक आजादी हासिल करने के तिब्बतियों के प्रयास का समर्थन करते हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रपति ओबामा चीन जन गणराज्य के भीतर तिब्बतियों के लिए वास्तविक स्वायत्तता हासिल करने के आपके मध यमार्गी मार्ग की सराहना करते हैं।''

दलाई लामा कार्यालय के बयान के मुताबिक, सुश्री जेरेट ने परमपावन को व्यक्तिगत रूप से यह संदेश दिया कि राष्ट्रपति ओबामा ''तिब्बती धर्म, भाषा और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा तथा मानवाधिकारों एवं नागरिक आजादी हासिल करने के तिब्बतियों के प्रयास का समर्थन करते हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रपति ओबामा चीन जन गणराज्य के भीतर तिब्बतियों के लिए वास्तविक स्वायत्तता हासिल करने के आपके मध्यमार्गी मार्ग की सराहना करते हैं।''

दलाई लामा के कार्यालय के एक वरिष्ठ अधि ाकारी के मुताबिक, ''सुश्री जेरेट ने कहा कि राष्ट्रपति ओबामा परमपावन के साथ स्थायी और चीन के साथ भी मजबूत रिश्ते चाहते हैं। अमेरिका बातचीत में प्रगति और तिब्बतियों के मानवाधिकारों एवं जीवन में सुधार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।''

बयान में यह भी कहा गया है कि ओबामा और दलाई लामा नवंबर में अमेरिका–चीन शिखर वार्ता के बाद वाशिंगटन, डीसी में मिलेंगे।

अधिकारी ने कहा, ''व्यापक मुद्दों को देखते हुए कुछ समय पहले यह फैसला लिया गया था कि बीजिंग में राष्ट्रपति ओबामा की बातचीत के बाद परमपावन और उनके बीच भेंट होनी चाहिए।''

परमपावन दलाई लामा के विषेश दूत लोडी ग्यारी के अनुसार, ''परमपावन ने अमेरिकी प्रतिनिधि ामंडल को अपने इन विचारों से अवगत कराया कि राष्ट्रपति किस तरह तिब्बती जनता की मदद कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे राष्ट्रपति से बीजिंग शिखर वार्ता के दौरान तिब्बत पर हुई चर्चा के बारे में जानना चाहेंगे। मेरे पास इस साल के बाकी दिनों के लिए दलाई लामा के कार्यक्रमों की सूची है और हम ह्वाइट हाउस के साथ बातचीत कर मुलाकात की तारीख तय करेंगे।''

केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के प्रमुख प्रो. सामदोंग रिंपोछे ने भी अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। उन्होंने कहा, ''यह यात्रा इस मायने में महत्वपूर्ण रही है कि राष्ट्रपति ओबामा ने परमपावन दलाई लामा के नेतृत्व और रवैए की सराहना की है तथा तिब्बती बौद्ध संस्कृति के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। हम अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के आभारी हैं कि वे परमपावन दलाई लामा और तिब्बती जनता को व्यक्तिगत रूप से संदेश देने के लिए इतनी दूर से आए।''

अमेरिकी अधिकारियों की दलाई लामा से भेंट पर चीन सरकार बिफरी

बीजिंग, 15 सितंबर चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जियांग यु ने कहा है कि चीन दलाई लामा और विदेशी प्रतिनिधियों के बीच किसी भी तरह की भेंट का सख्त विरोध करता है। मंगलवार को एक प्रेस वार्ता में उनसे जब अमेरिकी अधिकारियों और दलाई लामा के बीच हाल में हुई मुलाकात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ''तिब्बत मसले पर चीन का रवैया हमेशा स्पष्ट रहा है।''

जियांग ने कहा, ''हम किसी भी देश में चीन के खिलाफ दलाई लामा की अलगाववादी गतिविधियों के सख्त विरोधी हैं। हम चीन के आंतरिक मामले में इस मुद्दे के इस्तेमाल के भी विरोधी हैं।''

राष्ट्रपति ओबामा और तिब्बत पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की टिप्पणी

वॉल स्ट्रीट जर्नल, 16 सितंबर ओबामा प्रशासन सोचता है कि उसने तिब्बती नेता दलाई लामा की आगामी वाशिंगटन यात्रा के बारे में ठंडा रवैया अपनाकर विवेकपूर्ण राजनीति का परिचय दिया है। लेकिन सवाल यह है कि यदि अमेरिका के राष्ट्रपति धार्मिक आजादी का पक्ष नहीं लेंगे तो कौन लेगा?

इस हफ्ते के शुरू में ओबामा के एक सहायक ने तिब्बतियों से कहा कि राष्ट्रपति चीनी नेताओं से मिलने के बाद ही दलाई लामा से मिलेंगे। यह कुछ–कुछ वैसा ही है जैसाकि अमेरिकी प्रशासन ने

ईरान के डेमोक्रैटों का बुझे मन से समर्थन किया था और पुतिन के रूस तथा किम जोंग द्वितीय के उत्तरी कोरिया के साथ मैत्रीपूर्ण रवैया अपनाया था। यह दरअसल, एक महत्वपूर्ण परंपरा से हटना है। दलाई लामा जब भी वाशिंगटन की यात्रा पर आए, राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने उनसे मुलाकात की। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भी अपने कार्यकाल में ऐसा ही किया था। हालांकि तिब्बतयों ने राष्ट्रपति ओबामा के साथ दलाई लामा की मुलाकात औपचारिक रूप से तय नहीं की थी, लेकिन दलाई लामा ने अपनी वाशिंगटन यात्रा के दौरान राष्ट्रपति से मिलने की उम्मीद व्यक्त की थी।

श्री ओबामा चीनी टायर आयात पर शुल्क बढ़ाकर अब संभवतः मामले को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। या वे यह सोच रहे हैं कि तिब्बत के प्रति उदासीन रवैया अपनाने से चीन की नाराजगी खत्म हो जाएगी। या फिर वे महज चीन के दबाव के कारण दलाई लामा से नहीं मिलना चाहते। हाल के वर्षों में चीन 'अलगाववादी' दलाई लामा का स्वागत करने पर ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा और फ्रांस से अपनी कड़ी नाराजगी जता चुका है।

श्री ओबामा अगर दलाई लामा के साथ अपनी मुलाकात में विलंब कर रहे हैं तो इसका अर्थ यही है कि वे चीन के गुस्सैल रवैए के सामने झुक गए हैं। इसका नतीजा यह होगा कि वे जब भी दलाई लामा से मिलने की योजना बनाएंगे, चीन विरोध करेगा। इससे अन्य लोकतांत्रिक देशों में यह संदेश जाएगा कि चीनी दबाव के सामने झुकना स्वीकार्य है।

इस तस्वीर से यह भाव भी गायब है कि दलाई लामा का आंदोलन चीन और अमेरिका दोनों के हितों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दलाई लामा उन्ही मानव मूल्यों की वकालत करते है जिन पर अमेरिका की स्थापना हुईः यानी लोकतंत्र और पूजा की आजादी सहित बुनियादी नागरिक अधिकार। अगर चीन इन अधिकारों का सम्मान नहीं करेगा तो वहां स्थिरता और समृद्धि नहीं आएगी। चीन में अमन–चैन का होना सबके हित में है।

राष्ट्रपति ओबामा को कार्यभार संभाले हुए लगभग आठ महीने हो चुके हैं जबकि श्री बुश या श्री क्लिंटन ने राष्ट्रपति बनने के चार महीने के भीतर दलाई लामा से भेंट की थी। तिब्बती निश्चित रूप से जानते हैं कि भीतर ही भीतर क्या चल रहा है। प्रधानमंत्री सामदोंग ने मंगलवार को कहा भी था, ''अमेरिका सहित कई देश चीन के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं।'' क्या हम इस बदलाव में विश्वास कर सकते हैं?

अरुणाचल पर भारतीय नीति स्वागत योग्य

मजबूत होने का समय आया – टाइम्स आफ इंडिया

टाइम्स ऑफ इंडिया, 15 सितंबर चीन भारतीय प्रतिष्ठान के रवैए से एक बार फिर परेशान है। इस बार उसके परेशान होने की वजह यह है कि दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश में तावांग की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं। नई दिल्ली दलाई लामा की यात्रा में संभवतः किसी तरह की बाधा नहीं बनेगी। अरुणाचल प्रदेश पर दावा करने वाला चीन चाहता है कि भारत निर्वासित तिब्बती नेता को उस राज्य में जाने की इजाजत न दे। अभी पिछले साल दलाई लामा को उस क्षेत्र की यात्रा रद्द करनी पड़ी थी क्योंकि भारतीय प्रशासन ने चीन के कथित दबाव में उन्हें वहां जाने की इजाजत नहीं दी थी। लेकिन इस बार, भारत झुकने वाला नहीं है।

चीन उन मार्गदर्शक सिद्धांतों का हवाला देता रहता है जिन पर दोनों देश न सिर्फ तावांग बल्कि पूरे अरुणाचल प्रदेश से संबंधित विवाद को सुलझाने के लिए सहमत हुए थे। चीनी फौज ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपना हमला बढ़ा दिया है। इसके अतिरिक्त, चीन ने अरुणाचल प्रदेश को एशियाई विकास बैंक से मिलने वाले ऋण में रुकावट डालने की कोशिश की थी। इससे स्पष्ट है कि चीन भारतीय हितों को कोई तरजीह नहीं देता।

समय आ गया है कि भारत भी अपनी स्थिति को मजबूती से रखे। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। इसलिए भारत ही यह तय कर सकता है कि उस राज्य की यात्रा करने के लिए कौन आजाद है और कौन नहीं। आखिर, चीन यह आदेश देने वाला कौन होता है कि भारतीय क्षेत्र में दलाई लामा या उसकी नापसंद का कोई भी व्यक्ति यात्रा नहीं कर सकता।

भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि दलाई लामा उसकी धरती पर राजनैतिक अभियान नहीं चला सकते। दलाई लामा की अरुणाचल यात्रा धार्मिक मानी जा रही है। जब तक वे इस एजेंडे पर कायम हैं, उनकी यात्राओं पर प्रतिबंध लगाने का कोई कारण नहीं है। भारत के प्रशासनिक मामलों में दखल देकर उसे कूटनीतिक रूप से भड़काना चीन की रणनीति हो सकती है। जहां चीन ने अपने ज्यादातर पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद सुलझा लिया है, वहीं भारत एकमात्र अपवाद बना हुआ है। हाल ही में ताईवान ने बीजिंग की आपत्ति के बावजूद दलाई लामा को यात्रा की

समय आ गया है कि भारत भी अपनी स्थिति को मजबूती से रखे। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। इसलिए भारत ही यह तय कर सकता है कि उस राज्य की यात्रा करने के लिए कौन आजाद है और कौन नहीं। आखिर, चीन यह आदेश देने वाला कौन होता है कि भारतीय क्षेत्र में दलाई लामा या उसकी नापसंद का कोई भी व्यक्ति यात्रा नहीं कर सकता।

इजाजत दे दी, हालांकि उसके राष्ट्रपति मा यिंग–जोऊ चीन–समर्थक माने जाते हैं। नई दिल्ली को भी चीनी दबाव के आगे झुकने की जरूरत नहीं है।

तिब्बती नेता ने अरुणाचल पर चीन के दावे को थोथा बताया

मयंक अग्रवाल (आइएएनएस से साभार)

धर्मशाला, 16 सितंबर तिब्बत की निर्वासन सरकार के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है भारतीय सीमा के भीतर चीनी हमला गंभीर मामला है।

''अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और भारत एक प्रभुसत्ता–संपन्न राष्ट्र है। भारत में स्थायी रूप से रहने वाले लोगों को देश में कहीं भी जाने का अधिकार है। तो फिर चीन आपत्ति क्यों करता है?'' सामदोंग रिंपोछे ने सवाल किया।

उन्होंने आगे कहा, ''भारतीय मीडिया चीन की बातों को बेमतलब महत्व देता है। लेकिन वह बढ़ते चीनी हमलों पर ध्यान नहीं देता। यह मुझे बहुत हास्यास्पद लगता है। चीनी हमले अधिक गंभीर हैं।''

रिंपोछे ने कहा, ''परमपावन की अरुणाचल यात्रा विशुद्ध रूप से धार्मिक है। वे वहां अतीत में भी कई बार जा चुके हैं।''

तिब्बती प्रधानमंत्री ने अमेरिका सहित पश्चिमी देशों पर आरोप लगाया कि वे चीन के प्रति तुष्टिकरण की नीति अपना रहे हैं। उन्होंने कहा, ''आज आर्थिक हित अन्य हितों से अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए चीन के प्रति तमाम देशों ने तुष्टिकरण की नीति अपना ली है। चीन उन्हें धौंसबाजी दिखाता है और वे चुप रहते हैं। आज पश्चिमी देश चीन से डरे हुए हैं। आज समूची दुनिया 'समरथ को नहीं दोष गुंसाई' के सिद्धांत पर चल रही है।''

रिंपोछे ने आगे कहा, ''संयुक्त राष्ट्र के कथित मानवाधिकार घोषणापत्र को मानवाधिकारों के संरक्षण का पवित्र दस्तावेज माना जाता है। लेकिन तिब्बत में उस घोषणापत्र की प्रति रखने वाले भिक्षुओं को जेल में डाल दिया गया। चीन की इस हरकत की निंदा दुनिया में किसी ने भी नहीं की। पश्चिमी दुनिया के समर्थन से ही चीन की निरंकुश तानाशाही पिछले 60 वर्षों से चली आ रही है।''

इस बीच, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने नई दिल्ली से अनुरोध किया कि वह राज्य पर चीन के दावे के खिलाफ सख्त कदम उठाए और दलाई लामा की प्रस्तावित यात्रा के बारे में चीनी आपत्ति को खारिज कर दे। राज्य के मुख्यमंत्री दोर्जी खंडू ने आईएएनएस से कहा, ''अरुणाचल प्रदेश पर चीन का दावा आधारहीन और गलत है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और आगे भी बना रहेगा।''

''अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और भारत एक प्रभुसत्ता–संपन्न राष्ट्र है। भारत में स्थायी रूप से रहने वाले लोगों को देश में कहीं भी जाने का अधिकार है। तो फिर चीन आपत्ति क्यों करता है?'' सामदोंग रिंपोछे ने सवाल किया। उन्होंने आगे कहा, ''भारतीय मीडिया चीन की बातों को बेमतलब महत्व देता है। लेकिन वह बढ़ते चीनी हमलों पर ध्यान नहीं देता। यह मुझे बहुत हास्यास्पद लगता है। चीनी हमले अधिक गंभीर हैं।''

पूर्वोत्तर में भारत–तिब्बत सीमा पर भारतीय सेना को अलर्ट किया गया

नई दिल्ली, 11 सितंबर भारत अरुणाचल प्रदेश से संबंधित चीन के रुख के बारे में भले ही शोर न मचाए, लेकिन चीनी सेना से सुरक्षा के लिए भारतीय सेना पूर्वोत्तर में दो और डिवीजनें खड़ी कर रही है। इनमें लगभग 30,000 सैनिक होंगे।

भारतीय सेना ने इन खबरों के बाद कि चीन के 50,000 सैनिक तिब्बत में युद्धाभ्यास कर रहे हैं, भारत–चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर ऑपरेशनल एलर्ट कर दिया है। तिब्बत में चीन की गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं।

बताया जाता है कि चीनी युद्धाभ्यास के जवाब में भारतीय सेना भी अरुणाचल प्रदेश में ऑपरेशनल अभ्यास कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, नई डिवीजनों में से एक को अरुणाचल में तैनात किया जाएगा जो चीन–भारत–म्यांमार धुरी पर नजर रखेगी। दूसरी डिवीजन को इम्फाल से 20 किमी दूर लेईमखोंग में तैनात किया जाएगा। एक डिवीजन को खड़ा करने का काम जारी है।

सूत्रों के मुताबिक, हालांकि दोनों डिवीजनों में कुल मिलाकर एक कोर के बराबर सैनिक हो जाएंगे, लेकिन उन्हें अलग–अलग कर क्रमशः 3 कोर तथा 4 कोर के मातहत तैनात किया जाएगा। लेईमखोंग में तैनात की जाने वाली डिवीजन 3 कोर के नियंत्रण में होगी। 3 कोर नगालैंड में दीमापुर के पास रंगपहाड़ में स्थित है। अरुणाचल में तैनात होने वाली डिवीजन 4 कोर के मातहत होगी। 4 कोर अपर (ईस्टर्न) असम में स्थित है।

थल सेनाध्यक्ष जनरल दीपक कपूर ने आज कोलकाता में कोर कमांडरों और पूर्वी कमान के उच्चाधिकारियों से मुलाकात की। उल्लेखनीय है कि चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के समांतर राजमार्गों का निर्माण कर लिया है। इन राजमार्गों के संपर्कमार्गों को अरुणाल प्रदेश से जोड़ दिया गया है।

नई डिवीजन को तैनात करने और मौजूदा डिवीजन को बाहर भेजने से मणिपुर में उग्रवाद से लड़ाई में असम राइफल्स पर अनावश्यक और अतिरिक्त जिम्मेदारी आ जाएगी।

तिब्बत के मामले में पश्चिम चीन को तुष्ट कर रहा है : प्रो. सामदोंग रिंपोछे

अरुणाचल के मामले में चीनी घुड़कियों पर भारत की नीति को सराहा

धर्मशाला, 15 सितंबर तिब्बती प्रधानमंत्री प्रो. सामदोंग रिंपोछे ने इस बात पर दुख व्यक्त किया है कि तिब्बत के मामले में अमेरिका और अन्य कई पश्चिमी राष्ट्र चीन के प्रति तुष्टिकरण की नीति अपना रहे हैं। इसके पहले दलाई लामा कार्यालय ने बताया था कि तिब्बती नेता अगले महीने वाशिंगटन में राष्ट्रपति बराक ओबामा से नहीं मिलेंगे।

सन् 1991 से जॉर्ज एच. डब्लू. बुश सहित हर अमेरिकी नेता ने दलाई लामा की अमेरिका यात्राओं के दौरान उनसे भेंट की है। लेकिन इस बार व्हाइट हाउस से बताया गया कि राष्ट्रपति ओबामा का दलाई लामा से मिलने का कार्यक्रम नहीं है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका में दलाई लामा के बड़ी संख्या में समर्थक और अनुयायी हैं। इससे पहले समझाा जा रहा था कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता दलाई लामा की वाशिंगटन यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ओबामा के साथ उनकी मुलाकात होगी।

प्रो. रिंपोछे ने धर्मशाला में पत्रकारों के एक दल से कहा, ''कई राष्ट्र तुष्टिकरण की नीति अपना रहे हैं। . . .यहां तक कि अमेरिकी सरकार भी किसी–न–किसी तरह के तुष्टिकरण की नीति पर चल रही है। आज आर्थिक हित दूसरे हितों पर भारी पड़ रहे हैं।''

विश्लेशकों का कहना है कि यदि नवंबर में अमेरिकी राश्ट्रपति की पहली बीजिंग यात्रा से पहले ओबामा और दलाई लामा के बीच भेंट होती है तो चीन निश्चित रूप से नाराजगी व्यक्त करेगा। जाहिर है, ओबामा चीन के साथ मजबूत रिश्ते बनाने की जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, इससे उस पर तुशारापात हो सकता है।

दलाई लामा के कार्यालय ने सोमवार को एक बयान में कहा था कि परमपावन की योजना राष्ट्रपति ओबामा की चीन यात्रा के बाद उनसे भेंट करने की है। यह बयान दलाई लामा से अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात के बाद आया। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल दलाई लामा को तिब्बत संबंधी अमेरिकी नीति की जानकारी देने धर्मषाला आया हुआ था।

प्रतिनिधिमंडल की नेता ह्वाइट हाउस की सलाहकर वलेरी जेरेट थीं। मार्च 2008 में तिब्बत में अशांति फैलने के बाद वे धर्मशाला आने वाले किसी अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की सबसे वरिश्ठ अधिकारी हैं।

हालांकि दलाई लामा तिब्बत की आजादी के बजाय स्वायत्तता की मांग करते रहे हैं, इसके बावजूद चीन उन्हें 'अलगाववादी' मानता रहा है। उसने दलाई लामा से न मिलने के लिए ओबामा सहित विश्व नेताओं पर दबाव भी बढ़ा दिया है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक चीन ने मंगलवार को अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की धर्मशाला यात्रा की आलोचना की। उसने कहा कि वह दलाई लामा और विदेशी अधिकारियों के बीच किसी भी तरह की मुलाकात के खिलाफ है।

प्रो. रिंपोछे ने कहा कि ओबामा के साथ दलाई लामा की मुलाकात तय नहीं की गई है। उन्होंने कहा, ''मैं जानता हूं कि ओबामा अपनी चीन यात्रा से पहले दलाई लामा से क्यों नहीं मिलना चाहते हैं। यह उनकी समझदारी है। ओबामा के लिए अच्छा यही है कि वे चीनी नेतृत्व को नाराज न करें। दलाई लामा जहां भी जाते हैं, चीन बहुत परेशान हो जाता हैं।''

इस महीने के शुरू में दलाई लामा ने जब ताईवान की यात्रा की तो चीन ने उस कड़ी आपत्ति की। उसने ताईवान को चेतावनी दी कि इससे दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ सकती है।

भारत में दलाई लामा की नवंबर में अरुणाचल प्रदेश की प्रस्तावित यात्रा ने भी भारत और चीन के बीच एक विवाद पैदा कर दिया है। चीन अरुणाचल प्रदेश के एक विशाल हिस्से पर दावा करता है। भारतीय मीडिया की हाल की रिपोर्टों के अनुसार, चीनी सैनिकों ने सीमा पर हमला तेज कर दिया है।

चीन की आतत्तियों के जवाब में भारत ने कहा था कि ''अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और दलाई लामा भारत के एक सम्मानित मेहमान हैं। इसलिए मेहमान होने के नाते उन्हें भारत के किसी भी हिस्से की यात्रा करने की छूट है। प्रो. रिंपोछे ने भारत के इस नज़रिए का समर्थन करते हुए कहाा कि, ''भारत एक प्रभुसत्ता–संपन्न स्वतंत्र राष्ट्र है और वहां रहने वाले लोगों को देश के किसी भी हिस्से में जाने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि दलाई लामा की अरुणाचल प्रदेश यात्रा विशुद्ध रूप से धार्मिक है। परमपावन जी पहले भी वहां की यात्रा कर चुके हैं।''

भारतीय विश्लेशकों का कहना है कि दलाई लामा को अरुणाचल प्रदेश जाने की इजाजत देकर भारत इस राज्य पर अपनी नीति को स्पष्ट करना और उसपर अपने दावे की पुष्टि करना चाहता है।

प्रो. रिंपोछे ने धर्मशाला में पत्रकारों के एक दल से कहा, ''कई राष्ट्र तुष्टिकरण की नीति अपना रहे हैं। . . .यहां तक कि अमेरिकी सरकार भी किसी–न–किसी तरह के तुष्टिकरण की नीति पर चल रही है। आज आर्थिक हित दूसरे हितों पर भारी पड़ रहे हैं।''

चीन की नई ब्रह्मपुत्र योजना भारत और बांगलादेश के खिलाफ जलयुद्ध है

विवाद का नया खतरनाक आयाम — ब्रह्म चेलानी

चीन ब्रह्मपुत्र नदी को उत्तर की ओर मोड़ने पर विचार कर रहा है। अगर वह ऐसा करता है तो यह उसकी सबसे खतरनाक योजना होगी। चीन ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को सूखी पीली नदी की ओर मोड़ने के बारे में सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं करता। क्योंकि इस परियोजना से भारत के पूर्वोत्तर मैदानी इलाकों और पूर्वी बांगलादेश के पर्यावरण का विनाश अवश्यंभावी है। यह भारत और बांगलादेश के खिलाफ जलयुद्ध का ऐलान करने जैसा होगा।

चीन की हाइड्रो–इंजीनियरिंग परियोजनाएं और और अन्य योजनाएं यह दिखाती हैं कि भारत–चीन जल बंटवारे के केंद्र में तिब्बत है। लगभग 60 साल पहले तिब्बत दोनों देशों के बीच एक मध्यवर्ती देश था। लेकिन चीन के तिब्बत पर कब्जा करके उसका यह दर्जा खत्म कर दिया। इसके बावजूद, तिब्बत चीन और भारत के बीच राजनैतिक पुल बन सकता है। लेकिन यह तभी संभव है जब पानी टकराव की बजाय सहयोग का स्रोत बनेगा।

चीन और भारत की आर्थिक ताकत बढ़ने के कारण आज पूरी दुनिया की निगाहें इन्हीं दोनों देशों पर है। लेकिन उनके बीच की कड़वाहट और स्पर्धा पर लोगों का ध्यान बहुत कम जाता है।

अपनी ताकत बढ़ने के साथ चीन अपने एशियाई प्रतिद्वंद्वियों पर भारी पड़ने के लिए प्रतिबद्ध दिखता है। भारत के प्रति उसका सख्त रवैया इसकी मिसाल है। चीन की जन मुक्ति सेना विवादास्पद हिमालय सरहद पर आक्रामक गश्त लगाती है और नियंत्रण रेखा का बार–बार अतिक्रमण करती है। यही नहीं, चीनी सरकार भारत के अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताती है और राज्य नियंत्रित मीडिया में भारत के खिलाफ विषवमन करती है।

लेकिन भारत और चीन को बांटने वाले मुद्दे क्षेत्रीय विवादों से परे जाते हैं। भारत–चीन संबंधों में पानी एक प्रमुख सुरक्षा मुद्दा बनता जा रहा है जो जल्दी और आसानी से हल होने वाला नहीं दिखता।

चीन और भारत पानी की कमी वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं। सिंचित जमीन और जल–आधारित उद्योगों का विस्तार होने तथा उभरते मध्यम वर्ग की मांग बढ़ने से पानी के लिए गंभीर संघर्ष शुरू हो गया है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि दोनों देशों में पानी का शाश्वत संकट पैदा हो गया है जिससे निकट भविष्य में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता बहुत कम हो जाएगी। कुल मिलाकर पानी के मामले में दोनों देशों की स्थिति मध्य–पूर्व की तरह हो जाएगी।

यदि आज की रफ्तार से पानी की मांग बढ़ती रही तो जल संकट के कारण चीन और भारत का तेज आर्थिक विकास मंद पड़ सकता है। हालांकि ये दोनों देश अनाज निर्यात करते हैं, लेकिन जल संकट के के कारण इन्हें बड़े पैमाने पर अनाज आयात करना पड़ेगा। इससे वैश्विक खाद्य संकट और गंभीर हो जाएगा।

यह बात सही है कि भारत में चीन के मुकाबले खेती लायक जमीन अधिक है (चीन में 13.71 करोड़ हेक्टेयर और भारत में 16.05 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है)। लेकिन भारत की ज्यादातर प्रमुख नदियों के जल का स्रोत तिब्बत है। तिब्बती पठार की विाल हिमनदियां, विशाल भूमिगत सोते और विशाल ऊंचाई तिब्बत को ध्रुवीय हिमशिखर के बाद मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत बनाते हैं। गंगा को छोड़ एशिया की सभी प्रमुख नदियां तिब्बत के पठार से निकलती हैं। यहां तक कि गंगा की दो मुख्य सहायक नदियां भी तिब्बत से निकलती हैं।

लेकिन चीन अब अंतर्घाटी और अंतर्नदी जल स्थानांतरण परियोजनाओं को तिब्बत के पठार पर ले जा रहा है जिससे भारत और अन्य नदीतटवर्ती देशों में पानी का अंतरराष्ट्रीय बहाव रुक सकता है। इस तरह की हाइड्रो–इंजीनियरिंग परियोजनाओं के कारण जल–विवाद शुरू होने से पहले अच्छा यही होगा कि चीन अनुप्रवाह वाले राज्यों के साथ सहकारिता के आधार पर नदी–घाटी की व्यवस्था कर ले।

ऊर्ध्वप्रवाह वाले बांध, बैराज, नहरें और सिंचाई व्यवस्थाएं पानी को राजनैतिक हथियार बना सकती हैं जिसका इस्तेमाल खुले तौर पर युद्ध में हो सकता है। या शांति के समय में उसका इस्तेमाल नदीतटवर्ती राज्यों के खिलाफ असंतोष जताने में किया जा सकता है। यहां तक कि महत्वपूर्ण मौसम में हाइड्रोलॉजिकल डाटा मुहैया न करा कर भी पानी का इस्तेमाल राजनैतिक हथियार के रूप में किया जा सकता है। हाल के वर्षों में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में आई अचानक बाढ़ इस बात का प्रतीक थी क्योंकि चीन ने अपनी ऊर्ध्वप्रवाह वाली परियोजनाओं के बारे में भारत को कोई जानकारी नहीं दी। चीन की इस तरह की कार्रवाई से निपटने के लिए अनुप्रवाह वाले देश अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकते हैं।

दरअसल, चीन तिब्बत से निकलने वाली कई प्रमुख अंतरराष्ट्रीय नदियों को अवरुद्ध करता रहा है। यहां यह उल्लेखनीय है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण तिब्बत की नाजुक पारिस्थितिकी को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। जिन नदियों पर अभी तक हाइड्रो–इंजीनियरिंग का काम नहीं शुरू हुआ है वे सिंध ु और साल्वीन हैं। सिंधु नदी की घाटी ज्यादातर भारत और पाकिस्तान में पड़ती है। इसी तरह, साल्वीन बर्मा और थाईलैंड होकर बहती है। बहरहाल, युन्नान

प्रांत के स्थानीय अधिकारी भूकंप की संभावना वाले ऊर्ध्वप्रवाही क्षेत्र में साल्वीन नदी को अवरुद्ध करने पर विचार कर रहे हैं।

भारत सरकार पारदर्शिता और हाइड्रोलॉजिकल डाटा के बंटवारे के लिए चीन पर दबाव डालती रही है। वह चाहती है कि चीन न तो किसी नदी के प्राकृतिक बहाव को मोड़े और न ही सीमा पार जल प्रवाह में रुकावट डाले। लेकिन संयुक्त विशेशज्ञ स्तर की एक समिति भी जो हाइड्रोलॉजिकल डाटा पर संवाद और सहयोग के लिए 2007 में गठित की गई थी––इस काम में विफल साबित हुई है।

चीन ब्रह्मपुत्र नदी को उत्तर की ओर मोड़ने पर विचार कर रहा है। अगर वह ऐसा करता है तो यह उसकी सबसे खतरनाक योजना होगी। तिब्बती ब्रह्मपुत्र नदी को यार्लुंग त्सांगपो के नाम से जानते हैं। यह दुनिया की सबसे ऊंची नदी है। इसके अलावा, वह दुनिया की सबसे तेज बहाव वाली नदियों में भी शुमार है। चीन ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को सूखी पीली नदी की ओर मोड़ने के बारे में सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं करता क्योंकि इस परियोजना से भारत के पूर्वोत्तर मैदानी इलाकों और पूर्वी बांगलादेश के पर्यावरण का विनाश अवश्यंभावी है। इस तरह, ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव को मोड़ना भारत और बांगलादेश के खिलाफ जलयुद्ध का ऐलान करने जैसा होगा।

बहरहाल, सरकारी मदद से 2005 में प्रकाशित पुस्तक 'टिबेट्स वाटर विल सेव चाइना' में ब्रह्मपुत्र को उत्तर की तरफ मोड़ने की जोरदार वकालत की गई है। इसके अतिरिक्त, चीन हिमालय से होकर एक भूमिगत सुरंग निकालने के लिए ब्रह्मपुत्र को 'शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोटों'' के जरिए मोड़ना चाहता है। वह इस तरह का विचार नब्बे के दषक में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी) पर जिनेवा में आयोजित अंतरराश्ट्रीय समझौता वार्ता में व्यक्त कर चुका है। चीन ने शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोटों को सीटीबीटी से छूट देने अपील की थी। लेकिन वह अपने प्रयास में सफल नहीं हुआ।

मुद्दा अब यह नहीं है कि चीन ब्रह्मपुत्र के प्रवाह को मोड़ेगा या नहीं। मुद्दा यह है कि वह कब मोड़ेगा। जब अधिकारी संभावनाओं का अध्ययन कर लेंगे और डायवर्जन की योजना पर काम शुरू हो जाएगा, तो चीन इस परियोजना के निर्विवाद होने का ऐलान करेगा। चीन ने डायवर्जन पॉइंट के रूप में उस जगह की शिनाख्त पहले ही कर ली है जहां ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवशष करने से पहलं दुनिया की सबसे लंबी और गहरी घाटी बन जाती है।

तिब्बती पानी को उत्तर की तरफ मोड़ने की चीन की महत्वाकांक्षा को दो कारणों से बल मिला है। पहला, थ्री गोर्जेस डैम का पूरा होना जिसके बारे में चीन का दावा है कि महान दीवार के बाद यह उसकी महानतम उपलब्धि है। और दूसरा, राष्ट्रपति हु जिनताओ की नीति जिसकी पृष्ठभूमि में दो महत्वपूर्ण तत्व शामिल हैं पानी और तिब्बत। प्रशिक्षण से जलविज्ञानी हु 1989 में तिब्बत में मार्शल ला लगाने और निर्मम दमन चक्र चलाने के कारण कम्युनिस्ट पार्टी के पद–सोपान पर तेजी से ऊपर चढ़े।

चीन की हाइड्रो–इंजीनियरिंग परियोजनाएं और योजनाएं इस बात की द्योतक हैं कि तिब्बत भारत–चीन विवाद का केंद्र है।

(ब्रह्म चेलानी नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में सामरिक अध्ययन के प्रोफेसर हैं)

ताईवान में तिब्बती प्रदर्शनी

शरणार्थियों की सफलता की कहानी

ताईवान के नेशनल डेमोक्रेसी मेमोरियल हॉल में निर्वासित तिब्बतियों के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी में 400 से अधिक तस्वीरें, 20 से अधिक वृत्त चित्र और अनेक अनोखी चीजें प्रदर्शित की गईं।

निर्वासित तिब्बतियों की संस्कृति, धार्मिक जीवन और राजनीतिक प्रणाली पर आधारित 'लाइफ इन एक्साइल' नामक प्रदर्शनी का कल उद्घाटन किया गया। प्रदर्शनी का आयोजन दलाई लामा और उनके हजारों अनुयायियों के तिब्बत से भागकर भारत पहुंचने के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर किया गया।

दलाई लामा के तिब्बत धार्मिक फाउंडेशन के अध्यक्ष दावा सेरिंग ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ''तिब्बत पर चीनी कब्जे से आहत 80 हजार से अधिक तिब्बती नागरिक 1959 में भागकर भारत आए थे जिनमें से अधिकांश किसान और पशुपालक थे। उन्हें भारत जैसे मैदानी इलाकों में रहने का कोई अनुभव नहीं था।''

इस प्रदर्शनी में 400 से अधिक तस्वीरें और 20 से ज्यादा वृत्तचित्र थे जिनमें दिखाया गया कि किस तरह निवार्सन में रहते हुए भी तिब्बतवासियों ने अपनी संस्कृति और धर्म को संरक्षित रखा है, कैसे वे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

प्रदर्शनी देखने आए लोगों ने तस्वीरों के अलावा आजाद तिब्बत के सिक्के, नोट और स्टाम्प, भी देख सकेंगे। इसके साथ ही तिब्बत के पारम्परिक हस्तशिल्प, थांका पेंटिंग आदि प्रदर्शित किए गए।

तिब्बती पानी को उत्तर की तरफ मोड़ने की योजना को दो कारणों से बल मिला है। पहला, थ्री गोर्जेस डैम का पूरा होना जिसके बारे में चीन का दावा है कि महान दीवार के बाद यह उसकी महानतम उपलब्धि है। और दूसरा, राष्ट्रपति हु जिंताओ की नीति जिसमें दो महत्वपूर्ण तत्व शामिल हैं पानी और तिब्बत। 1989 में तिब्बत में मार्शल ला लगाने और निर्मम दमन चक्र चलाने के कारण कम्युनिस्ट पार्टी के पद–सोपान पर तेजी से ऊपर चढ़े।

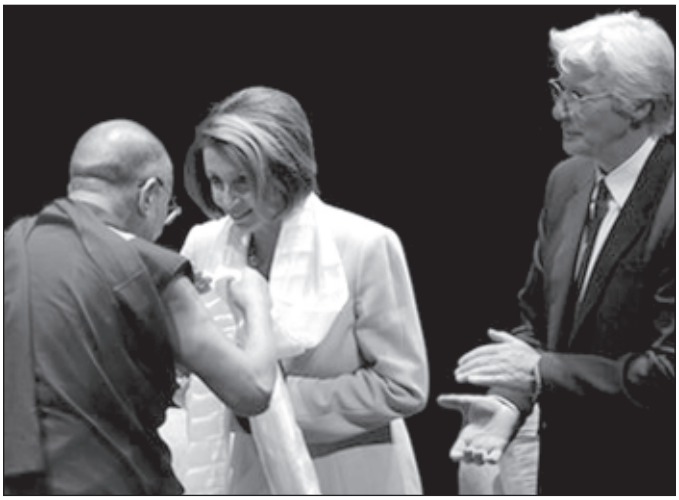

कैमरे की

1. मार्च 2008 के स्वतंत्रता प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए मौत की सजा से ठ
2. 7 अक्बूर को अमेरिकी संसद अध्यक्षा नैंसी पोलोसी को इंटरनेशनल कैंपेन
3. 13 अक्तूबर को अमेरिकी राष्ट्रपति की विशेष दूत सुश्री वेलेरी जेरेट और
4. दलाई लामा को अमेरिकी कांग्रेशनल गोल्ड मैडल की दूसरी सालगिरह प
5. चीन सरकार द्वारा तिब्बती प्रदर्शनकारियों को फांसी देने पर श्रद्धेय करमा
6. दलाई लामा की कनाडा यात्रा के दौरान 30 सितंबर को कैलगरी में स्थान
7. तिब्बती स्वतंत्रता प्रदर्शनकारियों को मौत की सजा दिए जाने के विरोध में
8. तिब्बती मामलों पर अमेरिका की नवनियुक्त दूत मारिया ओटेरो का स्वागत
9. विश्व भर में तैनात तिब्बती प्रतिनिधि कार्यालयों के अध्यक्षों ने 15–16 अक्
10. महिला नोबेल शांति विजेताओं जूड विलियम्स, मायरीड कोरिगान और शी

♦ आंखों देखी

आंख से

ोक पहले चीनी पुलिस के साथ शहीद लोयाक ल्हासा में।

फार टिबेट का 'लाइट आफ ट्रूथ' पुरस्कार देते लोडी ग्यारी और रिचर्ड गेअर।

उपविदेश मंत्री सुश्री मारिया ओटेरो का धर्मशाला में स्वागत करते दलाई लामा।

र 17 दिसंबर को काठमांडू में तिब्बतियों ने जुलूस निकाला।

पा ने शहीदों के लिए धर्मशाला में तीन दिन की प्रार्थना का आयोजन किया।

ोय रैड इंडियन समाज ने उनका स्वागत किया।

ब्रसेल्स में चीनी दूतावास के सामने तिब्बती युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया।

त करते हुए दलाई लामा के विशेष प्रतिनिधि लोडी ग्यारी वाशिंगटन में।

तूबर को धर्मशाला में दलाई लामा से मुलाकात की।

रीन एबादी ने 27 अक्तूबर धर्मशाला में दलाई लामा से मुलाकात की।

(फोटो परिचय : ऊपर बाएं से घड़ी की दिशा में)

सीमा पर चीन का दुस्साहस निरंतर जारी

चीनी आक्रामकता और भारतीय उपेक्षा ने भारत के लिए कई खतरे पैदा किए – भास्कर रॉय

(रीडिफ.कॉम से साभार), 18 सितंबर, 2009

हालांकि भारत–चीन सीमा का अभी परिसीमन किया जाना है और वास्तविक नियंत्रण रेखा स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं हुई है, लेकिन दोनों पक्षों को अच्छी तरह मालूम है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा कहां है। इससे भारत नियंत्रित क्षेत्र में गंभीर हमला रुक जाना चाहिए।

लेकिन समस्या यह है कि पिछले कुछ समय से चीन भारतीय क्षेत्र में गंभीर हमले करता रहा है। ये हमले लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हो रहे हैं जो भारत–चीन सीमा के पश्चिमी सेक्टर में आते हैं। चीन के इन हमलों का मकसद भारत की जमीन पर दावा करना है। पश्चिमी सेक्टर, मध्य सेक्टर और पूर्वी सेक्टर में वर्षों से छिटपुट हमले होते रहे हैं और भारत सरकार उनका विरोध करती रही है।

इस साल जुलाई से, भारतीय क्षेत्र पर चीनी अतिक्रमण की शैली में गुणात्मक बदलाव आया है। सो, भारतीय क्षेत्र में चट्टानों पर चीनी में लिखना, दो चीनी हेलिकॉप्टरों का भारत में घुस आना, चीन निर्मित डिब्बाबंद खाना गिराना और तीन चीनी लड़ाकू विमानों का दूसरी बार भारतीय सीमा में घुस आना बहुत गंभीर बात है। भारत सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

चीन पश्चिमी सेक्टर में दो महत्वपूर्ण कारणों से अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहता है। पहला, पाकिस्तान होकर फारस की खाड़ी में जाने के लिए काराकोरम हाईवे का इस्तेमाल। इस हाईवे के कारण चीन और फारस की खाड़ी की दूरी कम हो जाएगी।

भारतीय मीडिया के एक हिस्से में खबर छपी थी कि चीनी सैनिकों की फायरिंग में भारत–तिब्बत सीमा पुलिस के दो सैनिक घायल हो गए। लेकिन दोनों देशों ने इस खबर का खंडन कर दिया। ऐसे में भारत के आजाद मीडिया को अधिक जिम्मेदार बनने की जरूरत है।

चीन का नजरिया लंबे समय से यह रहा है कि ''यदि भारत पश्चिमी सेक्टर में रिआयत करता है तो चीन पूर्वी सेक्टर में रिआयत करने पर विचार करेगा।'' चीनी सरकारी मीडिया और विचारक अपने देश के इस नजरिए को प्रचारित करते रहे हैं। बहरहाल, चीन ने अपने नजरिए के बारे में विस्तार से कभी कुछ नहीं कहा। भारत और चीन के बीच दोनों सेक्टरों के नक्शों का आदान–प्रदान लंबित पड़ा हुआ है। लिहाजा यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा कहां से शुरू हो रही है और कहां खत्म।

चीन के लिए अपने दक्षिण–पश्चिम रणनीतिक विस्तार के संदर्भ में पश्चिमी सेक्टर का महत्व बढ़ गया है। वह पश्चिमी सेक्टर में अक्साई चिन के 38000 वर्ग किमी इलाके पर काबिज है जबकि उस पर भारत का दावा रहा है। चीन और पाकिस्तान को जोड़ने वाला ट्रांस–नेशनल काराकोरम हाईवे भी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से पाकिस्तान में प्रवेश करता है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर भारत अपना दावा जताता रहा है।

पाकिस्तान ने भारतीय दावे की अनदेखी करते हुए 1963 में एक समझौते के तहत अपने कब्जे वाले कश्मीर का 5000 वर्ग किमी भूभाग चीन को दे दिया।

अक्साई चिन चीन को तिब्बत होकर सिंजियांग तक भूतल परिवहन भी मुहैया कराता है। सिंकियांग के उइगुर मुसलमान इस प्रांत पर चीनी कब्जे का विरोध कर रहे हैं। बहरहाल, यह सड़क चीन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चीनी सैनिक इसके जरिए सिंकियांग में आसानी से आवाजाही कर रहे हैं। यही नहीं, उन्हें मध्य एशिया से लगी अपने देश की सीमा पर जाने में भी सहूलियत हो गई है।

चीन पश्चिमी सेक्टर में दो महत्वपूर्ण कारणों से अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहता है। पहला, पाकिस्तान होकर फारस की खाड़ी में जाने के लिए काराकोरम हाईवे का इस्तेमाल। इस हाईवे के कारण चीन और फारस की खाड़ी की दूरी कम हो जाएगी। चीन पाकिस्तान के ग्वादर में पहले ही एक बंदरगाह का निर्माण कर चुका है और काराकोरम हाईवे उससे जुड़ा हुआ है। उसकी योजना ग्वादर से पश्चिमी चीन तक तेल और गैस की जुड़वां पाइपलाइनें बिछाने की भी है। यह एक कड़ी चुनौती है लेकिन इन पाइपलाइनों का बिछ जाना इंजीनियरिंग की महान उपलब्धि होगी। इससे पहले चीन ने तिब्बत के ऊबड़–खाबड़ पठार के आर–पार रेलवे लाइन बिछाने का करिश्मा कर दिखाया है।

चीन के रणनीतिक महत्व के दो अन्य उद्देश्य भी हैं। पहला, भारतीय क्षेत्र में चीनी सीमा का अधिक से अधिक विस्तार करना। दूसरा,चीनी फौज को भारतीय भूमार्ग के बेहद करीब लाना और लद्दाख के दक्षिणी पूर्वी हिस्से को बाकी भारत से काटकर लद्दाख को कमजोर बनाना। यह कुछ–कुछ वैसा ही है जैसा पाकिस्तान ने 1999 में करगिल में करने की कोशिश की थी। उसने कश्मीर को जोड़ने वाले भूमार्ग को काटने की कोशिश की थी।

चीन ने सिक्किम के साथ लगी सीमा पर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है। 'फिंगर पॉइंट' क्षेत्र, जहां चीनी सैनिक बार–बार अतिक्रमण कर रहे हैं, दोनों

पक्षों के लिए सामरिक महत्व का है। 'फिंगर पॉइंट' सिक्किम और तिब्बत दोनों की सीमाओं के भीतर है।

हालांकि चीन ने 2003 में प्रधानमंत्री वाजपेयी की यात्रा के दौरान सिक्किम को भारत का अंग मान लेने का दिखावा किया, लेकिन हकीकत यह है कि उसने सिक्किम को भारत का अंग कभी नहीं माना। प्रधानमंत्री वाजपेयी और भारत सरकार चीन की इस चाल में आ गए कि यदि भारत तिब्बत को पूरी तरह चीन का अंग मान लेगा तो चीन भी सिक्किम पर भारत की प्रभुसत्ता को मान्यता दे देगा।

भारत ने तिब्बत को चीन का अंग मान लिया लेकिन चीन ने सिक्किम से संबंधित अपना वादा पूरा नहीं किया। वह हमेशा यही कहता रहा कि सिक्किम के मामले में कोई सीमा विवाद नहीं है। सिक्किम का मुद्दा भारत पर दबाव बनाने की चाल है और वह कभी भी ज्वलंत मसला बन सकता है। विवाद के नए क्षेत्र खोलना चीन की खतरनाक चाल है।

पूर्वी सेक्टर में, चीन 90,000 वर्ग किमी भूभाग पर अपना दावा करता है। यानी वह भारत के साथ सीमा विवाद और क्षेत्र विवाद को जिंदा रखने और उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाने के लिए समूचे अरुणाचल प्रदेश का इस्तेमाल कर सकता है। चीन ने ठीक यही किया जब उसने अरुणाचल प्रदेश में विकास कार्य के लिए एशियाई विकास बैंक से मिलने वाले ऋण में अड़ंगा लगाने की कोशिश की।

भारत ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि अरुणाचल प्रदेश उसका अंग है और उस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। हां, आबादी को छेड़े बिना सीमा पर छोटा–मोटा सामंजस्य बैठाया जा सकता है।

सीमा मसले को सुलझाने की रूपरेखा पर भारत–चीन के बीच 2005 में हुए समझौते में एक धारा यह है कि बसी हुई आबादी को छेड़ा नहीं जाएगा। हालांकि समझौता संयुक्त रूप से तैयार किया गया था, लेकिन चीन इस धारा का उल्लंघन कर रहा है। चीन का लक्ष्य तावांग को हासिल करना है क्योंकि वह उसे विशेष रणनीतिक महत्व का मानता है।

चीन का एक तर्क यह है कि छठे दलाईलामा तावांग में पैदा हुए थे, इसलिए तिब्बती उस जगह की बहुत कद्र करते हैं। उसका कहना है तिब्बतियों की भावनाएं तावांग से जुड़ी हैं, लिहाजा उसे तिब्बत का अंग होना चाहिए। चीन का यह तर्क खोखला है। इतिहास को देखें तो परम पावन व्यक्ति अपने जन्मस्थान को छोड़कर दूसरी जगह बस गए थे।

तावांग भारत, भूटान और तिब्बत की संधि पर बसा हुआ है। तावांग पर कब्जा हो जाने से चीन न केवल भूटान की पूर्वी सीमा पर, बल्कि सिलिगुड़ी में चिकन नेक नाम की पट्टी के किनारे भी अपनी फौज तैनात कर देगा। यह पट्टी पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती है। चीनी फौज युद्ध के समय में चिकन नेक पट्टी को आनन–फानन में काट सकती है क्योंकि ढाल के नीचे का कॉरिडोर कमजोर है।

चीन की योजना तिब्बत रेलवे को पूर्वी सेक्टर में भारतीय सीमा पर स्थित शिगात्से तक ले जाने की है। इससे चीनी फौज को लामबंद करने में बहुत मदद मिलेगी। इस बात को कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सकता है कि बीजिंग अपने 'फॉरवर्ड डिफेंस' के सिद्धांत के तहत भारत–हिमालय क्षेत्र को दक्षिण की तरफ ढकेल रहा है। गौरतलब है कि चीन भारत से लगी अपनी सीमाओं की किलेबंदी करता रहा है। लेकिन भारत जवाबी कार्रवाई करने से बचता रहा है।

भारत ने शायद ही किसी स्थायी ढांचे का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्रों में भारतीय गश्ती दल उस इलाके में भी नहीं जाते जिस पर कि भारत दावा करता है। कुछ इलाकों में वे बिना किसी हथियार के जाते हैं। इतना ही नहीं, कुछ अन्य हिस्सों में केवल नागरिक गश्त लगाते हैं।

कहा जाता है कि यह चीन को न भड़काने की सरकार की नीति है। दरअसल, भारतीयों ने अपनी कमजोरी का ही प्रदर्शन किया है जिसका चीनियों ने पूरा–पूरा लाभ उठाया है।

तिब्बती लेखकों के गायब होने को लेकर चीन से किए गए सवाल

न्यूयॉर्क की कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (सीपीजे) ने चीन के गांसू प्रांत के जन सुरक्षा ब्यूरो (पीएसबी) से यह बताने की मांग की कि अधिकारियों द्वारा पिछले माह हिरासत में लिए गए तिब्बती लेखक कुंगा सायांग कहां हैं और उनकी कानूनी स्थिति क्या है। आम्दो लबरांग ताशी खेल मठ के एक भिक्षु कुंगा ने राजनीतिक टिप्पणी लिखी थी। सीपेजे ने अपने बयान में कहा है कि कुंगा का गायब होना तिब्बती ऑनलाइन लेखकों के चल रहे उस सफाया अभियाना का ही हिस्सा है जो मार्च, 2008 में तिब्बत में पैदा हुई गंभीर अशांति के बाद शुरू किया गया है।

सीपीजे के एशिया समन्वयक बॉब डिएट्ज ने कहा, "हम कुंगा सायांग की हालत को लेकर चिंतित हैं। सयांग ऐसे तीसरे लेखक हैं जिन्हें हाल के दिनों में गांसू के अधिकारियों ने बिना किसी वजह बताए हिरासत में लिया है। हमने पीएसबी से कुंगा के बारे में पूरी जानकारी देने को कहा है।"

तावांग भारत, भूटान और तिब्बत की संधि पर बसा हुआ है। तावांग पर कब्जा हो जाने से चीन न केवल भूटान की पूर्वी सीमा पर, बल्कि सिलिगुड़ी में चिकन नेक नाम की पट्टी के किनारे भी अपनी फौज तैनात कर देगा। यह पट्टी पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती है। चीनी फौज युद्ध के समय में चिकन नेक पट्टी को आनन–फानन में काट सकती है क्योंकि ढाल के नीचे का कॉरिडोर कमजोर है।

तिब्बत के खनिज खजाने की चीनी लूट

केवल 'टार' मे ही अब तक 102 किस्म के खनिजों के भंडार मिले। चीन के आधे तांबा भंडार तिब्बत में

तिब्बत की कुलोंग तांबा अयस्क खान एशिया में सबसे बड़ी है। इसमें पक्के तौर पर 65 लाख टन तांबा है। वैसे, इस खान में कुल एक करोड़ टन तांबा होने का अनुमान है। तिब्बतियों के मुताबिक, खनिजों के भंडार वाले इलाकों से रेलवे का गुजरना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि रेलवे का निर्माण तिब्बतियों की सुविधा के लिए नहीं, बल्कि तिब्बत के प्राकृतिक संसाधनों को लूट के लिए किया गया है।

तिब्बत पर 1951 में जबरन कब्जा करके उसके एक तिहाई हिस्से से बनाए गए तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र 'टार' में निरंतर बहुमूल्य खनिजों के विशाल भंडार मिल रहे हैं। चीन के क्षेत्रीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ब्यूरो के अनुसार टार में 3 करोड़ टन से अधिक तांबा अयस्क के भंडार हैं। यह चीन के कुल तांबा अयस्क भंडार का आधे से अधिक है।

ब्यूरो के निदेशक ने बताया कि चीन में तांबे के सबसे अधिक भंडार तिब्बत में हैं। सन् 2008 तक वहां 329 तांबा अयस्क भंडार पाए गए थे जिनमें 11 बड़े और 6 मझोले आकार के थे। सन् 2001–05 में तिब्बती ताम्र अयस्क भंडार में लगभग एक करोड़ टन की वृद्धि हुई।

तिब्बत की कुलोंग तांबा अयस्क खान एशिया में सबसे बड़ी है। इसमें पक्के तौर पर 65 लाख टन तांबा है। वैसे, इस खान में कुल एक करोड़ टन तांबा होने का अनुमान है।

चीन की सातवीं सबसे बड़ी तांबा खनन कंपनी वेस्टर्न माइनिंग का इस खान में 58 प्रतिशत हिस्सेदारी है। कुलोंग से सांद्र तांबा के बजाय परिष्कृत, लगभग शुद्ध (इलेक्ट्रोलिटिक) तांबा निकलेगा। इससे इस खान का मूल्य बढ़ गया है।

इलेक्ट्रोलिटिक तांबे के एक हिस्से से सीधे तांबा वस्तुओं का निर्माण किया जाएगा। इससे खान और अधिक मुनाफे वाली हो जाएगी। तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की विशेष योजना 1996–2020 का अनुमान है कि युलोंग खान का जीवन 28 वर्षों का है।

लेकिन तिब्बत में बहुतायत में पाए जाने वाले तांबे, जस्ते, लोहे और सीसे के खनन की दुनिया भर के तिब्बतियों ने कड़ी आलोचना की है। इन धातुओं की खोज सरकारी भूवैज्ञानियों ने की है। गौरतलब है कि चीन ने 1951 में फौजी हमले के जरिए तिब्बत पर कब्जा कर लिया था।

चीन में तांबे का बहुत अभाव है, इसलिए उसे घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए हर साल बड़ी मात्रा में तांबे का आयात करना पड़ता है। चीन ने इस साल की पहली छमाही में पिछले साल की बनिस्बत लगभग 70 प्रतिशत अधिक तांबे का आयात किया। चीन ने जुलाई में 478,000 टन तांबे का आयात किया जबकि मई में उसने 422,000 टन का आयात किया था। इस साल पहली छमाही में उसने 22.35 लाख टन तांबे का आयात किया जो एक साल पहले के मुकाबले 68.9 प्रतिशत अधिक है।

विश्लेशकों के मुताबिक, चीन में खानों की बिक्री और देश के व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी खर्च के कारण तांबे के आयात में तेजी से वृद्धि हुई है।

तिब्बत में 600 अरब युवान मूल्य की खनिज संपदा

सितंबर में सिनहुआ की एक खबर के अनुसार तिब्बत में विविध तरह की खनिज संपदा है जिसका कुल मूल्य 600 अरब युआन (72.6 अरब डॉलर) से अधिक होने का अनुमान है।

तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के भू एवं संसाधन विभाग के अनुसार, तिब्बत 12 तरह के विविध खनिजों के भंडार के मामले में चीन के शीर्ष पांच स्थानों में आता है। क्रोम और तांबे के भंडार के मामले में तो वह पहले स्थान पर आता है। अभी तक इस क्षेत्र में 102 तरह के खनिज पाए गए हैं।

विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी दोरी ने कहा कि पूर्व तिब्बत स्थित युलोंग कॉपर प्रोडक्शन और दक्षिण मध्य तिब्बत स्थित न्याईसोंग आइरन प्रोडक्शन सहित खनिज औद्योगिक विकास के लिए नौ प्रमुख क्षेत्रों को चिह्नित किया गया है।

अधिकारी ने यह भी कहा कि ल्हासा की माइझोकुंगर काउंटी में और उत्तरी तिब्बत की लवण झीलों के इर्दगिर्द के इलाकों में स्थित खनन जोन खनिज संसाधनों के विकास के लिए राष्ट्रीय आधार बन सकते हैं।

तिब्बतियों ने 1142 किमी लंबी किंघाई–तिब्बत रेलवे के निर्माण का हमेशा विरोध किया है। उनका मानना है कि चीन का इरादा रेलवे के जरिए तिब्बत की विशाल प्राकृतिक खनिज संपदा को लूटना है।

तिब्बतियों के मुताबिक, खनिजों के भंडार वाले इलाकों से रेलवे का गुजरना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि रेलवे का निर्माण तिब्बतियों की सुविधा के लिए नहीं, बल्कि तिब्बत के प्राकृतिक संसाधनों को लूटने और खनिजों के आयात पर चीन की निर्भरता को कम करने के लिए किया गया है।

तिब्बतियों ने दूसरे कारणों से भी रेलवे के निर्माण का विरोध किया है। उन्हें आशंका है कि रेलवे के जरिए बड़ी संख्या में हान चीनी तिब्बत आकर बस जाएंगे। इससे तिब्बती अपने ही देश में हाशिए पर चले जाएंगे।

रेलवे से चीन को तिब्बती पठार के सैन्यीकरण में

भी मदद मिलेगी। रेलवे के जरिए पटरियों के किनारे बने प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों को सैनिकों और अन्य चीजों की अनवरत आपूर्ति की जाएगी। इस तरह चीन कब्जाए हुए तिब्बती पठार पर अपनी छावनी का विस्तार कर सकेगा और सैन्य क्षमता बढ़ा सकेगा।

मेलद्रो गोंगकार में खनन के खिलाफ निवासियों ने याचिका दी

धर्मशाला, 18 अगस्त (फायुल) मेलद्रो गोंगकार प्रांत के ग्यामा शहर के तिब्बती निवासियों ने स्थानीय सरकार को याचिका देकर उस इलाके में चल रही एक खनन परियोजना को तुरंत बंद करने की मांग की है। यह जानकारी तिब्बत की निर्वासन सरकार की वेबसाइट ने दी।

लेकिन चीन सरकार ने याचिका के जवाब में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। वह स्थानीय निवासियों की चिंताओं की जानबूझकर उपेक्षा कर रही है। पूरे क्षेत्र में चीनी फौज की कड़ी चौकसी है और बाहरी दुनिया से संवाद पर कड़ी पाबंदी है।

ऊपरी ग्यामा क्षेत्र में वाटर–डायवर्जन प्रोजेक्ट चला रही एक चीनी कंपनी के खिलाफ स्थानीय तिब्बती निवासियों ने इस साल 20 जून को विरोध प्रदर्शन किया था। इसके परिणास्वरूप क्रुद्ध तिब्बतियों और खनिकों के बीच झड़प हो गई जिसमें तीन तिब्बती घायल हो गए। इस परियोजना का उद्देश्य खनन स्थल की ओर पानी ले जाने के लिए रास्ता बनाना है। किसानों से उनके खेत बिना मुआवजे के जबर्दस्ती लेकर उन पर भारी–भरकम पाइपें बिछा दी गई हैं। इसके अलावा, ग्यामा शिंगचु नदी में विषाक्त कचरा जाने से पिछले साल बड़ी संख्या में मवेशियों की मौत हो गई।

घाटी के ग्रामीण पेयजल और सिंचाई के लिए ग्यामा शिंगचु नदी पर आश्रित हैं। लेकिन अत्यधिक खनन के कारण जल का स्रोत नष्ट हो गया है और नदी सूख गई है। सूत्रों के मुताबिक खानों की गहरी खुदाई के कारण उस क्षेत्र के कई झरने भी सूख गए हैं जिससे पेयजल का संकट पैदा हो गया है।

चीनी खनिकों ने तिब्बती निवासियों और तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र के अधिकारियों के बीच 21 जून को हुई बैठक के बाद खनन स्थल को खाली कर दिया था। लेकिन उन्होंने जल्दी ही फिर खनन शुरू कर दिया। उधर, चीनी अधिकारियों ने तिब्बतियों को धमकी दी कि यदि उन्होंने खनन में रुकावट डालने की कोशिश की तो उन पर 'अलगाववाद' का मामला चलाया जाएगा जिसमें बिना सुनवाई जेल की व्यवस्था है।

स्पेनी अदालत में चीन विरोधी मुकदमा

तिब्बत में चीन के मानवता विरोधी कदमों पर स्पेन की अदालत की जांच से चीन सरकार भड़की

मैड्रिड एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के अनुसार चीन ने स्पेन सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि तिब्बतियों पर चीन के पुलिस दमन के खिलाफ एक स्पैनिश अदालत की ओर से जारी जांच कार्य रोक दिया जाए।

चीनी अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय न्यायालय को भेजे गए एक दस्तावेज में स्पेन के एक न्यायाधीश के उस अनुरोध को ठुकरा दिया गया है जिसमें उसने चीनी रक्षा मंत्री लियांग गुआंगली समेत आठ चीनी नेताओं से जांच के सिलसिले में पूछताछ करने का अनुरोध किया था।

दस्तावेज के अनुसार चीनी अधिकारियों ने ''पारस्परिक न्यायिक सहयोग समझौते के दुरुपयोग और इस जांच कार्य को यथाशीघ्र रोकने के लिए त्वरित और प्रभावी कदमों'' को उठाने के लिए स्पेनिश सरकार से अपील की। एक तिब्बती मानव अधिकार समूह, द तिब्बत सपोर्ट कमेटी, ने तिब्बतियों पर चीनी दमन को 'मानवता के विरुद्ध अपराध' कहकर जुलाई 2008 मे कुछ चीनी नेताओं के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया था। यह मुकदमा बीजिंग ओलंपिक से ठीक पहले राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया था। पिछले साल तिब्बत में शातिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के चार दिनों बाद 14 मार्च को तिब्बत में अशांति पैदा हुई थी।

निर्वासित तिब्बती सरकार कहती है कि चीनी कार्रवाई में 203 तिब्बती मारे गए और करीब 1000 घायल हो गए, जबकि चीन सरकार जोर देती रही है कि केवल एक तिब्बती मारा गया था। उसने तिब्बती 'उपद्रवियों' पर 21 लोगों को मार डालने का आरोप लगाया। चीन की इस कार्रवाई से अंतरराष्ट्रीय विरोध शुरू हुआ, जिसके कारण अप्रैल में ओलंपिक मशाल की वैश्विक यात्रा बाधित हुई।

स्पेन के संविधान में 'वैश्विक क्षेत्राधिकार'' के तहत अत्याचार, आतंकवाद या युद्ध अपराधों के मामलों में न्यायालयों को राष्ट्रीय सीमाओं से परे जाने की अनुमति है। इसी सिद्धांत के तहत 2002 में गाजा में निर्मम हवाई हमलों के लिए इजरायल के खिलाफ जांच की गई थी। लेकिन अभियोजकों द्वारा मामले को बंद करने के निर्णय के बाद इसे बंद कर दिया गया।

द तिब्बत सपोर्ट कमेटी, ने तिब्बतियों पर चीनी दमन को 'मानवता के विरुद्ध अपराध' कहकर जुलाई 2008 मे कुछ चीनी नेताओं के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। स्पेन के संविधान में 'वैश्विक क्षेत्राधिकार'' के तहत अत्याचार, आतंकवाद या युद्ध अपराधों के मामलों में न्यायालयों को राष्ट्रीय सीमाओं से परे जाने की अनुमति है।

चार तिब्बती भिक्षुओं को दस वर्ष तक के कारावास की सजा मिली

चीन विरोधी प्रदर्शनों के बाद पकड़े गए

वॉयस ऑफ तिब्बत रेडियो सर्विस के मुताबिक, सेरा मठ के चार भिक्षुओं को दस वर्ष के कारावास की सजा दी गई है। इन भिक्षुओं ने पिछले साल 10 मार्च को दस अन्य भिक्षुओं के साथ तिब्बत की राजधानी ल्हासा के बारखोर मार्ग पर विरोध जुलूस निकाला था। पुलिस ने इन सभी भिक्षुओं को, जो तिब्बत का प्रतिबंधित राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए थे और तिब्बत की स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, तुरंत गिरफ्तार कर लिया था।

धर्मशाला, 21 अगस्त 2009 (फायुल) वॉयस ऑफ तिब्बत रेडियो सर्विस के मुताबिक, सेरा मठ के चार भिक्षुओं को दस वर्ष के कारावास की सजा दी गई है। इन भिक्षुओं ने पिछले साल 10 मार्च को दस अन्य भिक्षुओं के साथ तिब्बत की राजधानी ल्हासा के बारखोर मार्ग पर विरोध जुलूस निकाला था। पुलिस ने इन सभी भिक्षुओं को, जो तिब्बत का प्रतिबंधित राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए थे और तिब्बत की स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, तुरंत गिरफ्तार कर लिया था।

लोडो को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई और उन्हें फिलहाल ल्हासा के पास चुशुल जेल में रखा गया है। अधिकारियों ने शेरसुल (साचुखा) स्थिति लोडो के परिवार को अप्रैल में लोडो की सजा के बारे सूचित किया। उन्होंने लोडो की सजा के बारे में प्रचार करने के खिलाफ चेतावनी भी दी।

इस साल 14 जुलाई को जब लोडो का परिवार उनसे मिलने जेल गया, तो उन्हें पता चला कि दो अन्य भिक्षुओं––29 वर्षीय लोबसांग गोडुप और 30 वर्शीय मंगे सोएपा को पांच–पांच साल के कारावास की सजा मिली है।

साचुखा का एक निवासी ने, जो फिलहाल दक्षिण भारत के सेरा मठ में भिक्षु है, रेडियो को बताया कि थिनले नामग्याल नामक चौथे भिक्षु का कहीं पता नहीं है। थिनले पर पिछले साल ल्हासा में विरोध प्रदर्शन के दौरान एक घर में आग लगा देने का आरोप था।

उसी स्रोत ने बताया कि सोनम दाक्पा नामक एक अन्य भिक्षु को, जो कुछेक बार भारत की यात्रा कर चुका है, पिछले साल उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वे अशांति के दौरान तिब्बत लौट रहे थे। उन्हें दस साल के कारावास की सजा सुनाई गई। सोनम को चुशुल जेल में रखा गया है। चूंकि गिरफ्तार 14 भिक्षुओं में से ज्यादातर साचुखा के थे, इसलिए चीनी अधिकारियों को संदेह था कि उन भिक्षुओं को उकसाने में अरि रिंपोछे का हाथ है। पुलिस ने रिंपोछे को ल्हासा से गिरफ्तार कर लिया। अरि रिंपोछे साचुखा में वोंपो मठ के मुखिया हैं। गिरफ्तारी के बाद उनका भी कहीं अता–पता नहीं है। सेरा मठ के एक अन्य भिक्षु द्राखला को भी गिरफ्तार किया गया था। उनके भी ठौर–ठिकाने का कुछ पता नहीं है।

चीनी हिरासत में एक तिब्बती भिक्षु की यातना से मौत

टीसीएचआरडी, 10 सितंबर तिबेतन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स ऐंड डेमोक्रैसी (टीसीएचआरडी) को मिली विश्वसनीय सूचना के मुताबिक ल्हासा स्थित एक चीनी हिरासत केंद्र में द्रेपुंग मठ के एक तिब्बती भिक्षु की यातना से अगस्त 2009 में हुई।

बौद्ध भिक्षु की पहचान 32 वर्षीय काल्देन के रूप में की गई है। काल्देन ल्हासा के निकट गांव नंबर 8, त्सो–डो टाउनशिप के रहने वाले थे।

काल्देन ने 10 मार्च 2008 को द्रेपुंग मठ के 300 भिक्षुओं के साथ ल्हासा के सिटी सेंटर पर चीनी हुकूमत के खिलाफ एक मार्च में भाग लिया था। चीनी सुरक्षा बलों ने उन्हें और अन्य भिक्षुओं को गिरफ्तएउ कर लिया। उनकी गिरफ्तारी के बारे में न तो उनके परिवार के सदस्यों और न ही द्रेपुंग मठ के भिक्षुओं को सूचित किया गया।

उन्हें लंबे समय तक नजरबंद रखा गया था, यातनाएं दी गई थीं और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। उनके बड़े भिक्षु भाई, द्रेपुंग मठ के सांदुप को भी ल्हासा पुलिस ने 10 मार्च 2008 को गिरफ्तार कर लिया था। उनकी भी कोई खबर नहीं है।

चीन के सरकारी 'पंचेन लामा' का अभिषेक समारोह

26 जुलाई, चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार 'पंचेन लामा' ग्याल्सेन नोरबू का महत्वपूर्ण अभिषेक समारोह आयोजित किया गया। समारोह का आयोजन तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के शिगात्से स्थित ताशी लुंपो मठ में किया गया जो पंचेन लामा की परंपरागत पीठ है।

1995 में दलाई लामा ने पंचेन लामा के नए अवतारी बालक पांच वर्षीय गेदुन छयोकि नीमा की असली अवतार के रूप में पुष्टि की थी। लेकिन चीन सरकार ने तुरंत उस बच्चे और उसके माता पिता को गिरफ्तार करके उसकी जगह अपने एक पिठ्ठू बालक ग्याल्सेन नोरबू को असली 'पंचेन लामा' घोषित कर दिया। तब से गेदुन के बारे में एमनेस्टी इंटरनेशनल और यूरोपीय संसद के कई आग्रहों के बावजूद कोई खबर चीन सरकार ने नहीं दी है।

आयोजन स्थल पर करीब एक हजार से अधिक बौद्धभिक्षु और बौद्ध धर्मावलम्बी उपस्थित थे। समारोह दो घंटे तक चला। चीनी एजेंसी ने कुछ तिब्बतियों के हवाले से कहा कि ग्यारहवें पंचेन लामा ने बौद्ध धर्म

के अध्ययन और सांस्कृतिक ज्ञान के मामले में व्यापक अध्ययन कर लिया है। एजेंसी के अनुसार चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट, धार्मिक मामलों के राज्य प्रशासन, चीन के बौद्ध धर्मावलम्बियों के संघ एवं क्षेत्रीय सरकार के प्रतिनिधियों ने ग्याल्सेन नोरबू को शुभकामनाएं दीं। इस अभिषेक के बाद से ग्याल्सेन नोरबू को स्वायत्तशासी तिब्बत के अलावा चिंघाई, गांसु, सिचुआन और यून्नान के तिब्बती बहुल इलाकों के अनेक दौरे कराए गए हैं।

लेकिन जहां तक आम तिब्बती नागरिकों की बात है उन्होंने चीन की ओर से लादे गए दस तथाकथित 'पंचेन लामा' को स्वीकार नहीं किया है। पूरे तिब्बत में कहीं भी तिब्बती परिवार उनके फोटो नहीं लगाते जबकि गेदुन का फोटो रखने के अपनाध में आए दिन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है।

इससे पहले चीन के सरकारी समाचार पत्र 'चाईना डेली' में 23 मार्च को प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया था कि ग्याल्सेन नोरबू ने चीनी शासन की तारीफ के पुल बांधे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार ग्याल्सेन नोरबू ने कहा था कि तिब्बतियों के लिए बौद्ध धर्म का सार है – चीन की कम्युनिस्ट सरकार में आस्था व्यक्त करना।

चायना डेली के अनुसार ग्याल्सेन नोरबू ने खुद को 'प्राचीन तिब्बत के दमित दासत्व की संतति और दसवें पंचेन लामा का कानूनी उत्तराधिकारी' बताते हुए कहा कि वह 'इस क्षेत्र के लाखों दासों की मुक्ति की 50वीं वर्षगांठ' मनाते हुए उत्साहित हैं।

हालांकि एक अक्टूबर 1949 को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाईना के गठन के बाद से तिब्बत में जो भी परिवर्तन हुए उसे चीन ने सेना और दमनात्मक कार्रवाई के बल पर पूरा किया। इसके बावजूद इस लेख में लिखा गया है, ''तिब्बती समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को कठिनाई से हासिल उपलब्धियों को पहले से अधिक महत्व देना चाहिए तथा राष्ट्रीय एकता तथा तिब्बतियों की खुशी के लिए और अधिक योगदान करना चाहिए।''

पूर्वी तुर्किस्तान में 'अफवाह फैलाने वालों' को जेल में डालने की धमकी

बीजिंग, 9 सितंबर चीन ने एक बार फिर धमकी दी है कि सिंकियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र (पूर्वी तुर्किस्तान) की राजधानी उरुम्ची में 'अफवाह फैलाने वालों' को जेल में डाल दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि हाल में उरुम्ची में चीनी शासन के खिलाफ जबर्दस्त जातीय अशांति फैल गई थी जिससे चीन निपटने की पुरजोर कोशिश कर रहा है।

चाइना डेली में छपी एक खबर के मुताबिक, उरुम्ची में 'अफवाह फैलाने वालों के साथ अपराधियों जैसा बर्ताव किया जाएगा। अखबार के अनुसार, अधिकारियों ने कहा है, ''जो लोग जानबूझकर यह झूठी खबर फैला रहे हैं कि लोगों को सुइयां घोंपी जा रही हैं, उन्हें पांच साल तक की जेल की सजा दी जाएगी।'' सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने अपनी एक खबर में कहा कि जो लोग हमले में पीड़ित होने का नाटक करेंगे, उन्हें भी सजा दी जाएगी।

छह सौ अधिक लोगों ने, जिनमें लगभग सभी चीन से लाकर बसाए गए हान चीनी नागरिक हैं, दावा किया है कि हाल के हफ्तों में उइगुरों ने उन पर इंजेक्शन की सुइयों से हमला कर दिया। डॉक्टरों का कहना है कि अब तक 105 लोगों पर ''सूई घोंपने के स्पश्ट चिह्न दिखे हैं''। ये हमले उरुम्ची में तनाव पैदा होने के बाद हुए हैं।

इस साल जुलाई के शुरू में हुए दंगों के बाद उरुम्ची में स्थिति धीरे–धीरे सामान्य हो रही थी। उन दंगों में उरुम्ची के जातीय तुर्की अल्पसंख्यक उइगुरों के हाथों 200 से अधिक लोग मारे गए थे। मरने वालों में ज्यादातर हान चीनी थे। उइगुर सूत्रों के अनुसार जवाबी हमलों में चीनी सेना, पुलिस और चीन से लाकर बसाए गए हान लोगों ने 800 से अधिक उइगुरों की हत्या कर दी थी। सुइयों के हमले से उरुम्ची में फिर तनाव बढ़ गया है।

जुलाई के दंगों के बाद उरुम्ची में चीन सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया है। फेसबुक और ट्विटर सहित ज्यादातर सोशल नेटवर्किंग साइटें बंद हैं।

चीनी अधिकारियों के मुताबिक, आतंकित नागरिकों को आश्वस्त करने के लिए 7,000 'शांति दूत' भेजे गए हैं। अभी तक यह स्पश्ट नहीं है कि ये 'शांति दूत' पुलिस हैं, या सामाजिक कार्यकर्ता या कम्युनिस्ट पार्टी के काडर। लेकिन सिंकियांग कम्युनिस्ट पार्टी प्रमुख वांग लेकुअन ने कहा कि 'शांति दूत'' घर–घर जाएंगे और विवाद सुलझाएंगे।

चीन पिछले कुछ वर्षों में 'अफवाह फैलाने वालों' को सजा देने की कई बार धमकी दे चुका है। उसने पिछले साल तिब्बत में अशांति फैलने के बाद भी इस तरह की चेतावनी दी थी। सिन्हुआ के मुताबिक, सिचुआन में आए भूकंप के बाद अफवाह फैलाने वाले 17 लोगों को दंडित किया गया था। सरकार का अरोप था इन लोगों ने इंटरनेट पर 'गलत सूचना' डालकर, जनविश्वास तोड़ा था''।

इस साल जुलाई के शुरू में हुए दंगों के बाद उरुम्ची में स्थिति धीरे–धीरे सामान्य हो रही थी। उन दंगों में उरुम्ची के जातीय तुर्की अल्पसंख्यक उइगुरों के हाथों 200 से अधिक लोग मारे गए थे। मरने वालों में ज्यादातर हान चीनी थे। उइगुर सूत्रों के अनुसार जवाबी हमलों में चीनी सेना, पुलिस और चीन से लाकर बसाए गए हान लोगों ने 800 से अधिक उइगुरों की हत्या कर दी थी। सुइयों के हमले से उरुम्ची में फिर तनाव बढ़ गया है।

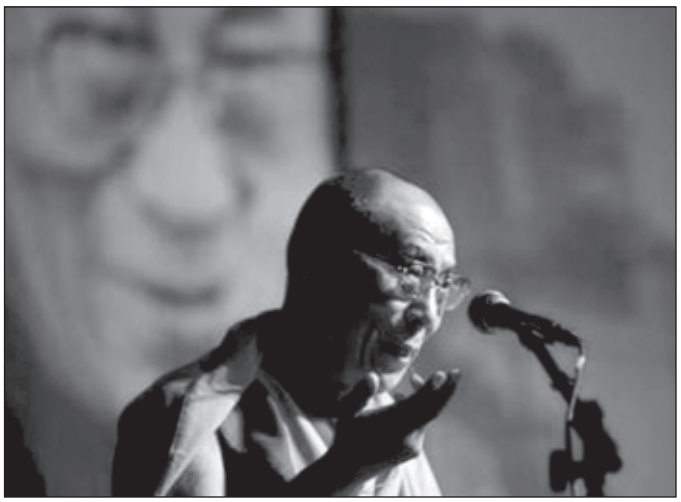

दलाई लामा एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में : विश्व नेता

दलाई लामा : भिक्षु जिससे 100 किताबें लिखने की प्रेरणा मिली

दलाई लामा के व्यक्तित्व और विचारों का दायरा

तिब्बत के निर्वासित शासक और धार्मिक नेता दलाईलामा, अगर पूर्व और पश्चिम के लेखकों को प्रेरित करते हैं तो यह शायद उनके लिए स्वाभाविक है। दलाईलामा पर अब तक 100 से अधिक किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। फिर भी लेखक उनसे साक्षात्कार के लिए लाइन लगाए हुए हैं।

धर्मशाला, 3 अगस्त (इंडो–एशिया न्यूज सर्विस से साभार) तिब्बत के निर्वासित शासक और धार्मिक नेता दलाईलामा, अगर पूर्व और पश्चिम के लेखकों को प्रेरित करते हैं तो यह शायद उनके लिए स्वभाविक है। दलाईलामा पर अब तक 100 से अधिक किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। फिर भी लेखक उनसे साक्षात्कार के लिए लाइन लगाए हुए हैं। धर्मशाला में जानकार लोग मानते हैं कि दलाई लामा पर दुनिया के किसी भी अन्य आध्यात्मिक गुरु की तुलना में अधिक जीवनियां लिखी गई हैं।

तिब्बत की निर्वासन सरकार के सूचना एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग के सचिव थुब्तेन साम्फेल ने आइएएनएस से कहा, ''मेरे ख्याल से परम पावन (दलाईलामा) पर 100 से अधिक जीवनियां लिखी जा चुकी है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि वे पूर्व और पश्चिम के लेखकों के आदर्श हैं। उनके लेखन और विचारों ने दुनियभर में लाखों लोगों को प्रभावित किया है। तिब्बत के लेखकों ने भी दलाईलामा पर बहुत सारी किताबें लिखी हैं।''

नोबेल शांति पुरस्कार विजेता दलाईलामा ने खुद दो आत्मजीवनियां ''माई लैंड ऐंड माई पीपुल'' और ''फ्रीडम इन एक्ज़ाइल''लिखी हैं। साम्फेल ने कहा, ''दलाईलामा की आत्मकथा ''माई लैंड ऐंड माई पीपुल'' और उनके धार्मिक उपदेश बौद्ध विद्वानों, विदेशी पर्यटकों, इतिहासकारों, दार्शनिकों, शिक्षकों और समाज सुधारकों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं।''

दलाईलामा ने ''माई लैंड ऐंड माई पीपुल'' निर्वासन में रहते हुए युवा व्यक्ति के रूप में लिखी थी। ''माई लैंड ऐंड माई पीपुल'' एक प्रतिष्ठित ग्रंथ है जिसमें यह बताया गया है कि अपने देश के अवतारी नेता के रूप में उनकी खोज किस तरह की गई। इसमें यह भी बताया गया है एक विनम्र भिक्षु विश्व नेता कैसे बना जो अपने देश को आजाद कराने के लिए आज तक संघर्ष कर रहा है।

केवल बौद्ध धर्म और दलाईलामा पर पुस्तकें बेचने वाले मकलोडगंज स्थित एक बुकस्टोर बुकवर्म के ल्हासांग त्सेरिंग ने कहा, ''दलाईलामा की जीवनी के अलावा बौद्ध धर्म के प्रेरणात्मक उपदेशों, धर्म, संस्कृति और विश्व शांति से संबंधित किताबों की भी बहुत मांग है।''

जिन पुस्तकों की बहुत मांग है, उनमें शिकागो स्थित भारतीय मूल के पत्रकार मयंक छाया की ''मैन, मॉन्क, मिस्टिक'', राजीव मेहरोत्रा संपादित ''इन माई ओन वर्ड्सः ऐन इंट्रोडक्षन टू माई टीचिंग्स ऐंड फिलॉसफी बाई दलाईलामा'', हार्पर कोलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित ''365 दलाईलामाः डेली एडवाइस फ्रॉम द हार्ट'', रोजर हिक्स और गाक्पा चोग्याम की ''ग्रेट ओशन'' और सर चार्ल्स बेल की ''पोट्रेट ऑव ए दलाईलामा'' शुमार हैं।

अमेरिकी पर्यटक जेम्स पुलित्जर, जो यहां दलाईलामा का साक्षात्कार लेने आए हुए थे, ने कहा, ''दलाईलामा पर लिखी किताब पढ़ने से ध्यान का अनुभव होता है। ऐसा लगता है मानो आप दलाईलामा से साक्षात्कार कर रहे हैं जिसमें वे आपको करुणा और सकारात्मक सोच पैदा करने के लिए निजी सलाह देते हैं। मैंने यह किताब ''द आर्ट ऑव हैप्पिनेस ऐट वर्क'' खास तौर पर खरीदी है। यह दरअसल उनकी पिछली पुस्तक ''द आर्ट ऑव हैप्पिनेस : ए हैंडबुक फॉर लिविंग'' के बाद की किताब है जिसमें सुख–शांति पर उनके संदेश हैं। इस पुस्तक में हॉवर्ड कटलर आध्यामिक गुरु के साथ कार्यस्थल पर सुख–शांति पाने के तरीके ढूढ़ते हैं। मैं भारत में अपनी छुट्टियों के दौरान पूरी पुस्तक को पढ़ डालूंगा।''

तिब्बत के पूर्वोत्तर स्थित ताक्तसेर पुरवे में 6 जुलाई 1935 को जन्मे 74 वर्षीय दलाईलामा ने सन् 1959 में चीनी शासन के खिलाफ तिब्बती जनांदोलन के विफल हो जाने के बाद तिब्बत से भागकर यहां तिब्बत की निर्वासन सरकार स्थापित की थी। आज लगभग 140,000 तिब्बती निर्वासन में रह रहे हैं। इनमें से 10,000 तिब्बती भारत के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं। तिब्बत में 60 लाख से अधिक तिब्बती हैं।